दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स बिहार

अप्रैल (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

बिहार 3

- बिहार सरकार द्वारा श्रमिकों की ट्रैकिंग का निर्णय 3
- साँप काटने से मौत पर परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपए 3
- बिहार राज्य सूचना आयोग के दो नए सूचना आयुक्तों ने ली शपथ 3
- बिहार विधानपरिषद 4
- निपुण बिहार योजना 4
- राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड-1 में बिहार 5
- बाबा केवल धाम राजकीय मेला 5
- बजट खर्च करने के मामले में बिहार 6 अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल 5
- बांका और पटना ज़िले में पुरातात्त्विक संरचनाओं के लिये जीपीआर सर्वेक्षण 6
- बिहार में कोरोनाकाल में बढ़ी बेरोज़गारी पर नियंत्रण 6
- मिथिला की 'रोहू' को जीआई टैग दिलाने की कवायद 7
- बिहार में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज 7
- बिहार राज्य वन्यप्राणी परिषद की 10वीं बैठक का आयोजन 7
- बिहार विधानपरिषद में दिलीप जायसवाल बने उपमुख्य सचेतक 8
- बिहार में लोहार जाति से छिना अनुसूचित जनजाति का दर्जा 8
- एल्बेंडाज़ोल 9
- बाबू वीर कुँवर सिंह विजयोत्सव 9
- बिहार संग्रहालय समिति की नवगठित शासी निकाय की पहली बैठक 9
- दरभंगा : मखाना हब 10
- धान की नई किस्म 'हीरा' का राष्ट्रीय स्तर पर चयन 10

नोट :

बिहार

बिहार सरकार द्वारा श्रमिकों की ट्रैकिंग का निर्णय

चर्चा में क्यों ?

31 मार्च, 2022 को बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने विधानपरिषद में बताया कि सरकार बिहार से बाहर काम करने वाले मज़दूरों की ट्रैकिंग कराएगी।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने बताया कि मज़दूरों की ट्रैकिंग के लिये पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसके आधार पर उनके हुनर का आकलन कर उन्हें काम दिया जाएगा।
- गौरतलब है कि कोरोना काल में अन्य राज्यों से लगभग 15 लाख मज़दूर लौटे थे। इनको रोज़गार प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कई प्रयास किये गए हैं।
- 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' के तहत 16 हज़ार लोगों का चयन कर स्वरोज़गार के लिये सरकार द्वारा दस लाख रुपए प्रदान किये जा रहे हैं, जिससे लगभग एक लाख 60 हज़ार युवकों को रोज़गार मिलेगा।
- इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 18 क्लस्टर बनाकर कोरोना काल में बिहार लौटे युवकों को रोज़गार देने की व्यवस्था की जा रही है।

साँप काटने से मौत पर परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपए

चर्चा में क्यों ?

31 मार्च, 2022 को बिहार की उपमुख्यमंत्री-सह-आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने विधानसभा में घोषणा की कि यदि राज्य में किसी भी व्यक्ति की कभी भी साँप के डसने से मृत्यु होती है, तो राज्य सरकार मृतक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देगी।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि बिहार में अब तक केवल बाढ़ अवधि में ही सर्पदंश पर अनुग्रह अनुदान का प्रावधान था।
- बाढ़ के दौरान सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपदा प्रबंधन विभाग इसे प्राकृतिक आपदाजनित कारण मानते हुए मृतक के परिजन को राज्य आपदा रिस्पांस कोष से निर्धारित सहाय्य मान दर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है।
- उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 मार्च, 2022 को आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय 24 मार्च, 2022 (अधिसूचना की तिथि) से प्रभावी हो गया है।

बिहार राज्य सूचना आयोग के दो नए सूचना आयुक्तों ने ली शपथ

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2022 को बिहार के राज्यपाल फग्गू चौहान ने फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण को राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलवाई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बिहार राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना जून 2006 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत की गई थी।
- गौरतलब है कि बिहार राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त सूचना आयुक्त के तीन पद हैं।
- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं।

बिहार विधानपरिषद

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2022 को बिहार विधानपरिषद की 24 सीटों के चुनाव के लिये मतदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- पिछले वर्ष विधानपरिषद के चुनाव स्थगित कर दिये गए थे, क्योंकि ग्रामीण स्थानीय निकाय, जो कुल निर्वाचक मंडल का लगभग 97.56% हिस्सा रखते हैं, को कोविड-19 महामारी के कारण पुनर्गठित नहीं किया जा सका था।
- गौरतलब है कि बिहार विधानपरिषद में कुल 75 सीट हैं, जिनमें से 63 निर्वाचित सदस्य तथा 12 मनोनीत सदस्य हैं।
- विधानपरिषद के एक सदस्य (Member of Legislative Council – MLC) का कार्यकाल छह वर्ष का होता है, जिनमें एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
- विधानपरिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से होता है-
- एक-तिहाई MLC राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं।
- इसके अलावा 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों, जैसे- नगरपालिका और ज़िला बोर्डों आदि द्वारा चुने जाते हैं।
- 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग करते हैं।
- 1/12 सदस्यों का निर्वाचन राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक करते हैं।
- शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है, जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव हो।

निपुण बिहार योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक समीक्षा बैठक में बिहार के सरकारी स्कूलों में जून के पहले सप्ताह में निपुण बिहार योजना लागू करने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत बच्चों को पढ़ने-लिखने, अक्षर पहचानने, उसका अर्थ बताने, जोड़-घटाव और आयु-सापेक्ष अन्य संख्यात्मक कार्यकलापों को हल करने में दक्ष बनाया जाएगा।
- इसके क्रियान्वयवन के लिये राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षा (मुख्य रूप से पहली से तीसरी कक्षा) के विद्यार्थियों के मध्य आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु निपुण भारत योजना प्रारंभ की गई है। इसे ही राज्य में 'निपुण बिहार' नाम से शुरू करने की योजना है।

नोट :

राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड-1 में बिहार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड-1 से संबंधित रिपोर्ट में बिहार को अचीवर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार की रैंक 15वीं, जबकि स्कोर 38.3 है।
- यह सूचकांक 2019-20 के आँकड़ों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है।
- गौरतलब है कि यह सूचकांक 6 मानकों- डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, नई पहल तथा पहुँच, वहनीयता एवं विश्वसनीयता के आधार पर जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए प्रयासों को ट्रैक करता है।
- विभिन्न मानकों के संदर्भ में बिहार का स्कोर निम्न प्रकार है-
- डिस्कॉम का प्रदर्शन- 61.3
- पहुँच, वहनीयता एवं विश्वसनीयता- 45
- पर्यावरणीय स्थिरता- 33.7
- ऊर्जा दक्षता- 22.8
- स्वच्छ ऊर्जा पहल- 4.9
- नई पहल- 7.6

बाबा केवल धाम राजकीय मेला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड अंतर्गत इंद्रवारा गाँव में मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने तीन दिवसीय बाबा केवल धाम राजकीय मेले का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- बाबा केवल धाम राजकीय मेला निषाद समाज का राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है।
- यह मेला चैत्र मास के नवरात्र में सप्तमी तिथि से शुरू होकर दसवीं तक आयोजित किया जाता है।
- 2010 में मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया था।
- बाबा केवल धाम क्षेत्र नून नदी के बाढ़ से प्रभावित रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए नदी के बाएँ और दाएँ तट का सुदृढ़ीकरण तथा उच्चीकरण किया गया है।

बजट खर्च करने के मामले में बिहार 6 अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2022 को बिहार राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने बताया कि सालाना बजट खर्च के मामले में बिहार नया कीर्तिमान बनाते हुए एक वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 6 अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सालाना बजट खर्च के मामले में बिहार से 5 राज्य आगे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं।
- गौरतलब है कि ये सभी राज्य पहले से ही विकसित राज्य की श्रेणी में आते हैं, साथ ही इनके पास औद्योगीकरण के साथ-साथ सी-पोर्ट की भी सुविधा है। सी-पोर्ट होने के कारण राज्य में ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है।
- वहीं, झारखंड के अलग होने के बाद से बिहार में भारी उद्योग की काफी कमी आ गई है। अभी तक इस कमी को दूर नहीं किया जा सका है।
- विजेंद्र यादव ने बताया कि साल 2005 से पहले राज्य सरकार 25 हज़ार करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाती थी। आमदनी भी 4 अंकों में ही सीमित थी, जो वर्तमान में 56 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुँच गई है।
- उन्होंने बताया कि राज्य के जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 17% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा निबंधन कर में 107%, ट्रांसपोर्ट कर और खान व भूतत्त्व कर में भी पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है।

बांका और पटना ज़िले में पुरातात्त्विक संरचनाओं के लिये जीपीआर सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पुरातत्त्व निदेशालय के निदेशक दीपक आनंद ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जीपीआर सर्वेक्षण में बांका के अमरपुर प्रखंड के भदरिया गाँव में जीपीआर सर्वेक्षण लगभग पूर्ण हो गया है, जबकि पटना ज़िले में सर्वेक्षण जल्द ही शुरू होगा।

प्रमुख बिंदु

- निदेशक आनंद ने बताया कि प्राचीन पटना, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र ज्ञान भूमि थी, जिसका संबंध आर्यभट्ट, वात्स्यायन और चाणक्य जैसे खगोलविदों एवं विद्वानों से रहा है।
- बांका में मंदार पर्वत के संबंध में उन्होंने बताया कि हिंदू पौराणिक कथाओं में कई संदर्भ हैं, जैसे- इस पहाड़ी का उपयोग समुद्र मंथन में किया गया था।
- गौरतलब है कि बांका के भदरिया गाँव का पुरातात्त्विक महत्त्व हाल ही में तब सामने आया, जब ग्रामीणों को कुछ प्राचीन ईंटों और ईंटों से बनी संरचनाएँ मिलीं। प्रारंभिक अध्ययनों के अनुसार यहाँ मिले अवशेष 2600 साल पुराने हैं।
- हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चानन नदी के तट पर खोजे गए पुरातात्त्विक स्थल का भी दौरा कर भदरिया गाँव स्थित स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी।
- जीपीआर एक भूभौतिकीय विधि है, जो ऊपरी सतह की छवि के लिये रडार पल्स का उपयोग करती है। यह गैर-विनाशकारी विधि रेडियो स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव बैंड (यूएचएफ/वीएचएफ आवृत्तियों) में विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग करती है और उपसतह संरचनाओं से परावर्तित संकेतों का पता लगाती है।
- यह तकनीक पुरातात्त्विक स्थलों और उनकी संरचना की पहचान करने में मदद करती है, जिससे संभावित उत्खनन से पहले प्राचीन बस्तियों और मानव निर्मित संरचनाओं की व्याख्या में सहायता मिलती है।

बिहार में कोरोनाकाल में बढ़ी बेरोज़गारी पर नियंत्रण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी द्वारा जारी आँकड़ों से पता चलता है कि बिहार में बेरोज़गारी दर मार्च 2022 में घटकर 14.4% पर आ गई है।

प्रमुख बिंदु

- आँकड़ों के अनुसार, मार्च 2020 में बिहार की बेरोज़गारी दर 15.4 % तथा अप्रैल-मई 2020 में 46% थी।

नोट :

- इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहार ने कोरोना काल में बढ़ी बेरोज़गारी को नियंत्रित कर लिया है, हालाँकि कोरोनाकाल में बढ़ी बेरोज़गारी को पूरी तरह घटाने के बाद भी बिहार में बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय औसत (8%) से अधिक है।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोज़गारी संबंधी आँकड़े निम्नलिखित हैं-

महीना	वर्ष	शहरी	ग्रामीण
मार्च	2020	15.7%	15.4%
मार्च	2022	17.9%	13.9%

मिथिला की 'रोहू' को जीआई टैग दिलाने की कवायद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मिथिला की 'रोहू' को जीआई टैग दिलाने के प्रयासों के तहत मछली विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- यह 'रोहू' बिहार में मिथिलांचल के दरभंगा और मधुबनी ज़िले के पुराने तालाबों में पाई जाती है।
- इस मछली का स्वाद अन्य की तुलना में काफी भिन्न होता है, जिसका कारण यहाँ का वातावरण, पुराने पोखरों की गाद और किनारों के फलदार वृक्ष है।
- बिहार में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 7% है, हालाँकि बिहार के भूगोल को देखते हुए यहाँ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं।
- गौरतलब है कि इस टीम का गठन उपमुख्यमंत्री सह-पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री तारकिशोर प्रसाद के निर्देश पर किया गया है।

बिहार में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज

चर्चा में क्यों ?

18 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की तर्ज़ पर ही बिहार सरकार द्वारा सभी राशन कार्डधारी परिवारों को सालाना पाँच लाख रुपए तक का फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि राज्य के 18 से 59 वर्ष के लगभग छह करोड़ लोगों को कोविड टीके का फ्री बूस्टर डोज़ लगाया जाएगा। इसके लिये कैबिनेट ने 1314.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
- गौरतलब है कि राज्य के 55% परिवार आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं, जिसमें 5 लाख तक के फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध है।
- राज्य में करीब 29% परिवार ऐसे हैं, जिन्हें आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिलता है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें भी यह सुविधा मिलनी चाहिये। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा पाँच लाख रुपए तक का फ्री इलाज उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।

बिहार राज्य वन्यप्राणी परिषद की 10वीं बैठक का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

18 अप्रैल, 2022 को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य वन्यप्राणी परिषद (Bihar State Wildlife Board) की 10वीं बैठक मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में बिहार राज्य वन्यप्राणी परिषद की 9वीं बैठक (अगस्त 2020) में लिये गए फैसलों पर अब तक की प्रगति पर राज्य वन्यप्राणी परिषद के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह सदस्य सचिव प्रभात कुमार गुप्ता ने प्रजेंटेशन दिया।
- बैठक में कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी, विक्रमशिला गांगेय डॉलफिन आश्रयणी, रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी तथा राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी के अंतर्गत वन्यप्राणी क्लियरेंस संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
- साथ ही कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी को टाइगर रिज़र्व बनाने संबंधी प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यप्राणी परिषद को भेजने तथा जान-माल को क्षति पहुँचाने वाले घोड़परास एवं जंगली सुअर को वर्मिन घोषित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि सहरसा ज़िला के आरण गाँव में मोर के संरक्षण और पुनर्वास के लिये केंद्र स्थापित करने का बैठक में विशेष आग्रह किया गया।

बिहार विधानपरिषद में दिलीप जायसवाल बने उपमुख्य सचेतक

चर्चा में क्यों ?

18 अप्रैल, 2022 को बिहार विधानपरिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के आदेश के बाद दिलीप जायसवाल को उपमुख्य सचेतक और नीरज कुमार व रीना देवी को सचेतक बनाने की अधिसूचना जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री और सदन के नेता नीतिश कुमार ने विधानपरिषद में दिलीप जायसवाल को उपमुख्य सचेतक और एमएलसी (MLC) नीरज कुमार व रीना देवी को सचेतक पद पर मनोनीत किया।
- गौरतलब है कि मुख्य सचेतक और सचेतक वह राजनीतिक व्यक्ति होता है, जो सदन में पार्टी के अनुशासन और व्यवहार के लिये ज़िम्मेदार होता है। आमतौर पर सचेतक पार्टी के सदस्यों को मुख्य मुद्दों पर पार्टी के विचार के साथ बने रहने, पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही किसी मुद्दे पर सदन में मत डालने का निर्देश देता है। कभी-कभी सदन में ऐसी परिस्थिति और मुद्दे आते हैं, जहाँ पर वोट के बँटवारे का डर दल को होता है।
- पार्टी के सदस्य सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान न करें, इसलिये मुख्य सचेतक व्हिप जारी करता है। व्हिप के खिलाफ मतदान करने पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों और विधानसभा के सदस्यों को वोट डालने के लिये कोई व्हिप जारी नहीं किया जा सकता।

बिहार में लोहार जाति से छिना अनुसूचित जनजाति का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2022 को बिहार सरकार ने आदेश जारी कर लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) का दर्जा वापस ले लिया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है।
- गौरतलब है कि बिहार में लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था।
- प्रदेश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य के मामले में 21 फरवरी, 2022 को अपने फैसले में राज्य सरकार के वर्ष 2016 के आदेश को निरस्त कर दिया।
- सामान्य प्रशासन विभाग के इस निर्णय के तहत लोहार जाति के दूसरी पिछड़ी जातियों की तरह एनेक्सचर वन में शामिल होने से अब लोहार जाति को अन्य पिछड़े वर्गों के तहत आने वाली अन्य जातियों की तरह ही सुविधाएँ दी जाएंगी।

नोट :

- अनुच्छेद 366 (25) ने अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों के रूप में परिभाषित किया है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है

एल्बेंडाज़ोल

चर्चा में क्यों ?

22 अप्रैल, 2022 को बिहार के मुंगेर में शाह जुबैर मध्य विद्यालय घोरघट में एल्बेंडाज़ोल दवा खिलाने से 50 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए।

प्रमुख बिंदु

- एल्बेंडाज़ोल कृमि मुक्ति का एक साक्ष्य-आधारित, विश्व स्तर पर स्वीकृत, प्रभावी समाधान है, जिसका उपयोग सभी बच्चों में कृमि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है।
- इसी संदर्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस (National Deworming Days) शुरू किया गया, जो प्रति वर्ष 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य 1-19 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में आँतों के कीड़े, जिन्हें मिट्टी-संचारित हेल्मिंथ्स (एसटीएच) के रूप में भी जाना जाता है, का उन्मूलन करना है।
- गौरतलब है कि आँतों के कीड़े परजीवी रूप में मानव आँतों में रहते हैं और पोषक तत्त्वों और विटामिन का उपभोग कर बच्चों को कुपोषित बनाते हैं।

बाबू वीर कुँवर सिंह विजयोत्सव

चर्चा में क्यों ?

23 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुँवर सिंह विजय उत्सव को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु

- यह वीर कुँवर सिंह की जन्म व कर्मभूमि जगदीशपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया 164वाँ विजयोत्सव था।
- इस विजयोत्सव में एक साथ 77 हज़ार 993 झंडे फहराकर सर्वाधिक झंडे फहराने का रिकॉर्ड बनाया गया।
- उल्लेखनीय है कि वीर कुँवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था।
- 1777 ई. में बिहार के भोजपुर ज़िले के जगदीशपुर गाँव में जन्में वीर कुँवर सिंह का प्रभावक्षेत्र बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, आज़मगढ़, बलिया, गाज़ीपुर में भी था।

बिहार संग्रहालय समिति की नवगठित शासी निकाय की पहली बैठक

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार संग्रहालय समिति की नवगठित शासी निकाय की प्रथम बैठक संपन्न हुई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस दिन राज्य के बच्चे/बच्चियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा।

नोट :

- साथ ही बैठक में महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को, बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को एवं बिहार दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को बिहार म्यूजियम (संग्रहालय) में नि:शुल्क भ्रमण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना म्यूजियम (संग्रहालय) का भी विस्तार करने के साथ ही पटना म्यूजियम (संग्रहालय) और बिहार म्यूजियम (संग्रहालय) को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि बाहर से आने वाले लोग दोनों संग्रहालयों का एक साथ अवलोकन कर सकें।
- गौरतलब है कि इस वर्ष जनवरी में बिहार संग्रहालय के शासी निकाय की संरचना में परिवर्तन करते हुए इसके अध्यक्ष पद का दायित्व मुख्यमंत्री को सौंपा गया था, जो कि पूर्व में विकास आयुक्त के पास था। साथ ही, संग्रहालय के निदेशक के पदनाम को परिवर्तित कर महानिदेशक किया गया था।

दरभंगा : मखाना हब

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2022 को दरभंगा के सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने केंद्र सरकार की '10,000 नई एफपीओ योजना का गठन और संवर्धन' योजना के तहत दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र में एकदिवसीय कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यशाला का उद्देश्य ज़िले में मखाना उत्पादक किसानों का सहकारी कृषक उत्पादक संगठन बनाकर दरभंगा को मखाना हब के रूप में विश्वपटल पर स्थापित करने हेतु उपायों पर विचार करना है।
- गौरतलब है कि 'एक ज़िला एक उत्पाद' के अंतर्गत मखाना के उत्पादन एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये दरभंगा ज़िला को प्रधानमंत्री द्वारा एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- इस अवसर पर सांसद डॉ. ठाकुर ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाने से मखाना एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के वैश्विक व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 6,865 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ की गई थी।
- इसके तहत वर्ष 2020-21 में FPOs के गठन हेतु 2200 से अधिक FPOs उत्पादन क्लस्टरों का आवंटन किया गया है।
- इसके तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है-
- 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रति FPO के लिये 18.00 लाख रुपए का आवंटन।
- FPO के प्रत्येक किसान सदस्य को 2 हज़ार रुपए (अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति एफपीओ) का इक्विटी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- FPO को संस्थागत ऋण सुलभता सुनिश्चित करने के लिये पात्र ऋण देने वाली संस्था से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी सुविधा का प्रावधान किया गया है।

धान की नई किस्म 'हीरा' का राष्ट्रीय स्तर पर चयन

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2022 को हैदराबाद में आयोजित समन्वित चावल सुधार परियोजना की 57वीं वार्षिक धान शोध बैठक में धान की नई किस्म 'हीरा' का चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिये किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस नई किस्म का विकास भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमराँव के वैज्ञानिक डॉ. प्रकाश सिंह और उनकी टीम द्वारा किया गया है।
- धान की यह किस्म बाढ़ के पानी में 15 दिनों तक डूबी रहने के बाद भी खराब नहीं होगी।
- इसकी उत्पादन क्षमता भी सामान्य धान से डेढ़ गुना अर्थात् 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

नोट :